



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22022025-261229  
CG-DL-W-22022025-261229

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22—फरवरी 28, 2025 (फाल्गुन 3, 1946)  
No. 08] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22—FEBRUARY 28, 2025 (PHALGUNA 3, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, .....	69	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, .....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, .....	161	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, .....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, .....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, .....	1311	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, .....	447
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, .....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, .....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, .....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, .....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, .....	673
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण, .....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	69	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	161	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1311	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	447
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	673
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2025

संख्या 9-7/2024-यू.3(क)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा के किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, भारतीय मानव बस्ती संस्थान (एक गैर-लाभकारी कंपनी) द्वारा यूजीसी पोर्टल पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस), केंगेरी के साथ-साथ भारतीय मानव बस्तियाँ संस्थान (आईआईएचएस), बेंगलुरु को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. और इसके अतिरिक्त, जबकि मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, भारतीय मानव बस्ती संस्थान (प्रायोजक निकाय) को एक घटक इकाई (अर्थात् आईआईएचएस केंगेरी परिसर) के साथ आईआईएचएस, बेंगलुरु को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय के रूप में संस्थान का दर्जा देने से पहले तीन साल की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र जारी किया था।

4. और जबकि, निदेशक, आईआईएचएस, बेंगलुरु ने एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा सत्यापित किया गया था। आयोग ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट की स्वीकृति के संबंध में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा भारतीय मानव बस्तियों के लिए संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक के साथ-साथ भारतीय मानव बस्तियों के लिए संस्थान (आईआईएचएस), केंगेरी (घटक इकाई) को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- i. संपूर्ण चल और अचल संपत्ति भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक के नाम पर होगी।
- ii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय माने जाने वाले किसी भी संस्थान या उसकी घटक इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iii. भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- iv. भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस), बेंगलुरु, कर्नाटक में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- v. भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक केवल वर्तमान में उभरते नए क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।
- vi. भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता प्रदान करने के लिए सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों का मूल्यांकन करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और संस्थान को समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।
- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, जैसा भी मामला हो, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं जारी रहेंगी और भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- viii. जब भी आवश्यक हो, भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतन या संशोधित या परिवर्तित करेगा।

- ix. भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस) बेंगलुरु, कर्नाटक को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दें और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।

पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 7th February 2025

No. 9-7/2024-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application was submitted by the Indian Institute for Human Settlements (a not-for-profit company) on UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category to Indian Institute for Human Settlements (IIHS), Bengaluru along with Indian Institute for Human Settlements (IIHS), Kengeri under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And further whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent to Indian Institute for Human Settlements (sponsoring body) for fulfillment of the certain conditions within a period of three years before granting of Institution deemed to be University status under distinct category to IIHS, Bengaluru along with a constituent unit (i.e. IIHS Kengeri campus).

4. And whereas, Director, IIHS, Bengaluru submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI which was verified by UGC Expert Committee. The commission considered and approved the report of the UGC Expert Committee regarding acceptance of compliance report of the Institution.

5. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declare Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka along with Indian Institute for Human Settlements (IIHS), Kengeri (constituent unit) as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:—

- i. The entire moveable & immovable assets shall be in the name of Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka.
- ii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University or of its constituent units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iii. Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- iv. The academic programmes to be offered at Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- v. Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka shall not keep confined only to presently new emerging areas but make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.
- vi. Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka.
- viii. As and when necessary, Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

- xi. Indian Institute for Human Settlements (IIHS) Bengaluru, Karnataka shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE  
Joint Secy.